

II. सकल मांग*

अनियमित निवेश मांग के चलते 2012-13 की पहली तिमाही में सकल मांग की स्थिति कमजोर हुई। कंपनियों की बिक्री में काफी गिरावट आई। राजकोषीय मोर्चे पर घाटा संबंधी संकेतकों में काफी वृद्धि हुई। जहां मंदी ने परोक्ष करों- उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों- को प्रभावित किया वहीं सार्वजनिक खर्च, विशेष रूप से सब्सिडी की मात्रा ऊंची रही। सरकार द्वारा हाल में किये गये प्रयास, विशेष रूप से ईंधन की सब्सिडियों के संबंध में किये गए प्रयास स्वागतयोग्य हैं, परंतु ये 2012-13 में राजकोषीय संकेतकों के असंतुलन को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। शीघ्र ही और उपाय किए जाने की जरूरत है।

निजी उपभोग तथा निवेश में निरंतर गिरावट

II.1 जीडीपी के व्यय खंड की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई और 2011-12 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी तिमाही के

9.0 प्रतिशत से घटकर यह 3.9 प्रतिशत रह गया (सारणी II.1)। निजी अंतिम खपत व्यय तथा सकल नियत पूंजी निर्माण में 2012-13 की पहली तिमाही में कमी आई। इनमें पिछले वर्ष भी कमी आई थी। इनका जीडीपी में क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत हिस्सा होता है।

II.2 निवेश में आई गिरावट का कारण गैर-मौद्रिक था, जैसा कि पिछली रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है, हालांकि इसमें ब्याज दरों का असर भी था। साथ ही, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जिसमें सब्सिडी जैसे अंतरण वाले भुगतान शामिल नहीं होते), जिसका जीडीपी में लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा होता है, में 2011-12 की पहली तिमाही में तेजी से वृद्धि हुई जो अंशतः आधार प्रभाव की वजह से थी।

सारणी II.1: जीडीपी का व्यय पक्ष (2004-05 के मूल्यों पर)

मद	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13
			ति1	ति2	ति3	ति4	
1	2	3	4	5	6	7	8
वृद्धि दरें							
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	9.6	6.9	9.0	6.9	6.2	5.6	3.9
कुल खपत व्यय	8.1	5.4	4.9	4.9	6.1	5.8	4.7
(i) निजी	8.1	5.5	4.9	4.6	6.4	6.1	4.0
(ii) सरकारी	7.8	5.1	4.9	7.2	4.7	4.1	9.0
सकल अचल पूंजी निर्माण	7.5	5.5	14.7	5.0	-0.3	3.6	0.7
स्टॉक में परिवर्तन	37.4	2.4	7.1	2.8	0.4	-0.4	-1.2
मूल्यवान वस्तुएं	32.4	7.9	9.8	9.4	2.9	9.3	-55.4
निवल निर्यात	5.5	-30.7	-23.2	-46.7	-117.9	117.8	-2.1
विसंगतियां	38.9	-112.7	-51.8	-119.6	-152.0	-124.0	-123.7
तुलनात्मक हिस्सा							
कुल खपत व्यय	70.1	69.1	70.1	70.8	72.7	63.6	70.6
(i) निजी	58.7	57.9	59.5	60.3	60.4	52.2	59.5
(ii) सरकारी	11.4	11.2	10.6	10.5	12.5	11.4	11.1
सकल अचल पूंजी निर्माण	32.5	32.0	33.9	33.4	30.3	30.9	32.8
स्टॉक में परिवर्तन	3.7	3.5	3.7	3.6	3.4	3.4	3.5
मूल्यवान वस्तुएं	2.4	2.4	2.6	2.7	2.1	2.2	1.1
निवल निर्यात	-6.0	-7.4	-8.6	-11.3	-11.1	0.6	-8.5
विसंगतियां	-2.5	0.3	-1.7	0.8	2.6	-0.6	0.4
ज्ञापन:							
बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (₹ बिलियन में)	52368	55959	13174	13111	14377	15296	13693

*: त्वरित अनुमान। #: संशोधित अनुमान।

नोट: चूंकि सारणी में केवल प्रमुख मदों को ही शामिल किया गया है, इसलिए आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।

* ज्ञात सीमाओं के बावजूद, जीडीपी के व्यय पक्षीय आंकड़ों का उपयोग सकल मांग के घटकों के प्रॉक्सी के रूप में किया गया है।

सारणी II.2: जीडीपी के व्यय पक्ष की योगदान-भारित वृद्धि दरें (2004-05 के मूल्यों पर)*

(प्रतिशत)

मद	2011-12				2012-13
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
1	2	3	4	5	6
1. निजी अंतिम खपत व्यय	3.0	2.8	3.9	3.2	2.4
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	0.5	0.8	0.6	0.5	1.0
3. सकल अचल पूंजी निर्माण	4.7	1.7	-0.1	1.1	0.2
4. स्टॉक में परिवर्तन	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
5. मूल्यवान वस्तुएं	0.3	0.2	0.1	0.2	-1.5
6. निवल निर्यात (i-ii)	-1.8	-3.8	-6.4	4.0	-0.2
(i) निर्यात	3.9	4.4	1.5	4.6	2.4
(ii) आयात	5.7	8.2	7.9	0.6	2.6
7. योग (1 से 6)	7.0	1.8	-2.0	9.0	1.9
8. विसंगतियां	2.0	5.1	8.2	-3.4	2.1
9. बाजार मूल्य पर जीडीपी (7+8)	9.0	6.9	6.2	5.6	3.9

*: जीडीपी के व्यय पक्ष के घटक की योगदान-भारित वृद्धि दरें इस प्रकार हैं:

(घटक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन) x स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें)

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।

II.3 निवल निर्यातों एवं मूल्यवान वस्तुओं के भारित योगदान में 2012-13 की पहली तिमाही में जो गिरावट आई वह भुगतान संतुलन में आई गिरावट के अनुरूप थी, लेकिन यह पिछली तिमाही के आंकड़ों के ठीक विपरीत है (सारणी II.2)। उल्लेखनीय है कि व्यय संबंधी आंकड़ों में विसंगति बनी हुई है। सारणी से स्पष्ट होता है कि 2012-13 की पहली तिमाही में व्यय संबंधी विभिन्न घटकों की योगदान-भारित वृद्धि दरों का योग 1.9 प्रतिशत बनता है जो निवल परोक्ष करों के समायोजन के बाद जीडीपी की उत्पादन पद्धति (आपूर्ति पक्ष) से परिकलित 3.9 प्रतिशत से काफी कम है। चूंकि उत्पादन पद्धति से परिकलित जीडीपी को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में बेहतर अनुमान के रूप में माना जाता है, अतः आपूर्ति पक्ष से प्राप्त व्यय पक्षीय जीडीपी तथा विभिन्न घटकों से प्राप्त जीडीपी के बीच के अंतर को सांख्यिकीय विसंगति के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। इस विसंगति का प्रमुख कारणों में व्यय घटकों के सटीक आंकड़े उपलब्ध न होना तथा सीएसओ द्वारा सकेतक आधारित पद्धति को अपनाया जाना है। ऐसे बड़े अंतर के कारण मौद्रिक नीति के लिए अर्थव्यवस्था में सकल मांग के आकलन का कार्य जटिल हो जाता है।

लाभ में गिरावट तथा मार्जिन में कमी के साथ-साथ बिक्री में आई गिरावट कमजोर मांग को दर्शाती है

II.4 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री में आयी गिरावट मांग में आई गिरावट को दर्शाती है। 2012-13 की पहली तिमाही में बिक्री में वृद्धि की दर घटकर 13 प्रतिशत रह गई जो पिछली 10 तिमाहियों में सबसे कम है (सारणी II.3)। इसके अतिरिक्त, बिक्री की तुलना में व्यय में वृद्धि की दर अधिक होने से निवल लाभ में 10.7 प्रतिशत की गिरावट आई। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर निवल लाभ में गिरावट की स्थिति को देखें तो गिरावट की दर और तेज अर्थात् 18 प्रतिशत रही (सारणी II.4)।

II.5 बिक्री की तुलना में लाभ में वृद्धि की दर (ईबीआईटीडीए/ईबीआईटी/निवल लाभ) कम रहने से लाभ मार्जिन (बिक्री के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए/ईबीआईटी/निवल लाभ) में गिरावट आई। बिक्री की तुलना में विक्रेय माल में परिवर्तन के अनुपात में आई गिरावट क्षमता के कम उपयोग की स्थिति के अनुरूप है जैसा कि आदेश बहियों, इंटेंटियों एवं क्षमता के उपयोग संबंधी सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है और यह स्थिति आगे मांग की स्थिति संबंधी धारणा में गिरावट को दर्शाती है (चार्ट II.1)।

II.6 190 कंपनियों की 2012-13 की दूसरी तिमाही के प्रारंभिक परिणाम दर्शाते हैं कि इन कंपनियों की बिक्री की वृद्धि दर में गिरावट

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13

समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां द्वितीय
तिमाही की समीक्षा 2012-13

सारणी II.3: कंपनी क्षेत्र-वित्तीय निष्पादन

मद	2011-12	2011-12				2012-13
		ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
1	2	3	4	5	6	7
कंपनियों की संख्या	2308					
वृद्धि दरें¹ (प्रतिशत में)						
बिक्री	18.8	22.3	19.3	19.3	15.3	13.0
व्यय, जिसमें से	21.4	22.8	22.7	24.9	16.4	15.3
कच्चा माल	22.6	28.0	23.1	25.0	16.1	13.0
स्टाफ लागत	17.4	19.0	18.0	18.6	14.4	17.5
बिजली और ऊर्जा	28.2	31.1	26.2	30.4	25.4	17.7
परिचालन लाभ (ईबीडीआईटीडीए)	1.1	12.6	-0.8	-5.5	-0.8	-4.1
अन्य आय*	49.3	63.5	25.6	69.9	47.5	29.4
मूल्यहास	10.6	11.4	9.8	10.3	10.7	9.5
सकल लाभ (ईबीआईटी)	4.5	18.2	-0.1	-2.2	3.3	-3.0
ब्याज	40.3	34.1	47.4	43.6	36.7	36.3
कर प्रावधान	6.3	22.0	4.0	-2.6	2.9	-5.5
निवल लाभ	-11.9	7.1	-15.3	-30.5	-7.9	-10.7
चयनित अनुपात						
बिक्री की तुलना में स्टाक में परिवर्तन #	1.3	1.4	0.5	2.3	1.0	0.8
ब्याज का बोझ	26.7	23.4	28.5	28.5	26.8	32.9
ब्याज कवरेज	3.7	4.3	3.5	3.5	3.7	3.0
बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	13.4	15.0	12.9	12.6	13.1	12.7
बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	12.1	13.3	11.4	11.2	12.4	11.4
बिक्री की तुलना में निवल लाभ	6.4	7.6	6.1	4.9	6.9	6.0

#: इस मद की जानकारी स्पष्टतः सूचित करने वाली कंपनियों के लिए।

*: यदि स्पष्टतः उल्लेख न किया गया हो तो अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है।

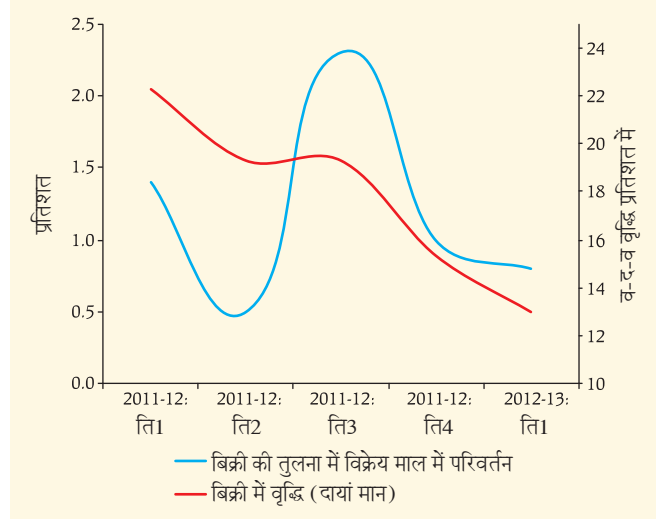
1. वृद्धि दरें कंपनियों के कॉमन सेट के लिए पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में संदर्भाधीन अवधि में स्तर में प्रतिशत परिवर्तन हैं।

सारणी II.4: कारपोरेट क्षेत्र वित्तीय निष्पादन (आनुक्रमिक वृद्धि)

संकेतक	सामान्य कंपनियां (तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि, प्रतिशत में)				
	2011-12				2012-13
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1
1	2	3	4	5	6
कंपनियों की संख्या	2308				
बिक्री	-2.9	3.4	5.6	8.7	-4.8
व्यय, जिसमें से	-3.6	4.9	7.7	6.8	-4.5
कच्चा माल	-3.3	1.1	8.3	9.7	-5.9
स्टाफ लागत	2.7	6.7	3.1	1.3	5.4
बिजली और ऊर्जा	13.5	-3.0	7.9	5.5	6.6
परिचालन लाभ (ईबीडीआईटीडीए)	-4.9	-10.8	3.0	13.5	-8.1
अन्य आय	-9.6	7.7	4.8	44.5	-20.7
मूल्यहास	-1.9	0.6	3.7	8.2	-3.0
सकल लाभ (ईबीआईटी)	-6.3	-11.2	3.1	20.5	-12.1
ब्याज*	8.4	8.0	3.1	13.3	8.0
कर प्रावधान	5.0	-11.3	-4.5	15.6	-3.6
निवल लाभ	-15.1	-16.3	-15.1	52.5	-17.7

*: कुछ कंपनियां निवल आधार पर ब्याज की सूचना देती हैं।

चार्ट II.1: बिक्री की तुलना में बिक्री की वृद्धि में उतार-चढ़ाव तथा विक्रेय माल में परिवर्तन



जारी रही (सारणी II.5)। निवल लाभ की वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परंतु, ये प्रारंभिक परिणाम उन थोड़ी कंपनियों के हैं जो समग्र कंपनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

सारणी II.5: कारपोरेट क्षेत्र - 2012-13 की दूसरी तिमाही के शुरुआती परिणाम

मद	वृद्धि दरें (प्रतिशत में)		
	2011-12	2012-13	
	ति2	ति1	ति2
1	2	3	4
कंपनियों की संख्या	190		
बिक्री	28.9	16.1	13.5
व्यय, जिसमें से	32.6	19.8	15.7
कच्चा माल	39.6	20.7	15.8
स्टाफ लागत	22.0	23.1	23.0
बिजली और ऊर्जा	21.9	8.1	12.5
परिचालन लाभ (ईबीआईटीडीए)	11.7	2.0	8.4
अन्य आय*	77.6	37.5	30.7
मूल्यहास	5.8	-2.6	-3.4
सकल लाभ (ईबीआईटी)	21.6	8.6	15.4
ब्याज	57.6	33.0	-5.2
कर प्रावधान	24.7	6.8	12.0
निवल लाभ	15.9	7.9	21.6
चयनित अनुपात			
बिक्री की तुलना में स्टॉक में परिवर्तन#	1.2	1.2	2.3
ब्याज का बोझ	9.8	10.0	8.1
ब्याज कवरेज	10.2	10.0	12.4
बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	15.8	14.4	15.0
बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	15.1	14.2	15.4
बिक्री की तुलना में निवल लाभ	10.3	9.8	11.0

#: इस मद की जानकारी स्पष्टतः सूचित करने वाली कंपनियों के लिए।

*: यदि स्पष्टतः उल्लेख न किया गया हो तो अन्य आय में असाधारण आय/व्यय को शामिल नहीं है।

1. वृद्धि दरें कंपनियों के कॉमन सेट के लिए पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में संदर्भाधीन अवधि में स्तर में प्रतिशत परिवर्तन हैं।

2012-13 की पहली तिमाही में निवेश का स्तर कम रहा

II.7 नए कंपनी निवेश हेतु प्रमुख बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में गिरावट 2012-13 की पहली तिमाही में भी जारी रही (सारणी II.6)। जहां अनुमोदनों की संख्या में तेजी से गिरावट आई वहीं तिमाही के दौरान परियोजनाओं की अनुमानित लागत में मामूली वृद्धि हुई। निवेश के इरादे का उद्योग-वार विश्लेषण दर्शाता है कि सकल परिकल्पित निवेश में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक था (चार्ट II.2)।

हाल के उपायों के बावजूद 2012-13 में राजकोषीय लक्ष्य की प्राप्ति में आशंका

II.8 वर्ष 2012-13 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान केंद्र सरकार के घाटा संकेतकों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि

सारणी II.6: संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं और उनके द्वारा परिकल्पित लागत (तिमाही-वार)

वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना संबंधी व्यय # (₹ बिलियन)
1	2	3
2011-12	ति1	154 (131)
	ति2	194
	ति3	151
	ति4	169 (153)
2012-13	ति1*	80
		268

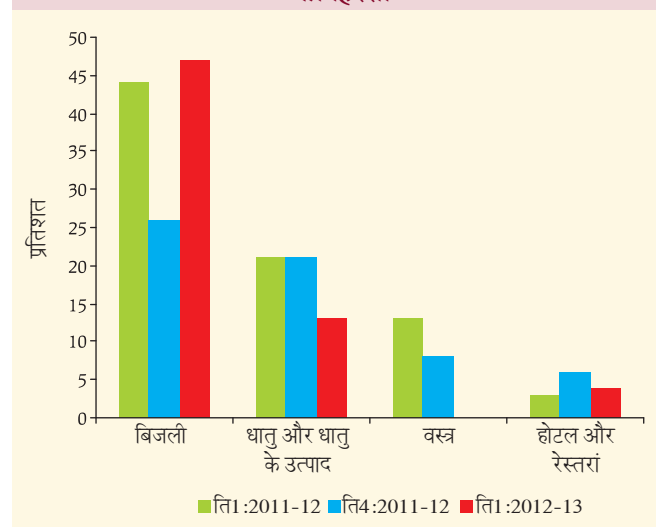
#: 39 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़ों पर आधारित।

*: ति 1: 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं एवं 32 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ति 1: 2011-12 एवं ति 4: 2011-12 के समान आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं।

हुई (सारणी II.7)। राजकोषीय समेकन के पूर्वनिर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक स्थिति भिन्न रही क्योंकि 2012-13 के पहले पांच महीनों का राजकोषीय घाटा समग्र वर्ष के अनुमान का लगभग दो-तिहाई रहा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2012-13 में केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी/ जीडीपी) पिछले वर्ष की स्थिति से उल्लेखनीय रूप से बेहतर रहने की संभावना नहीं है। यह स्थिति, सितंबर 2012 के मध्य से किए गए उपायों के अतिरिक्त, इस दिशा में और शीघ्र उपाय किए जाने की जरूरत को रेखांकित करती है।

II.9 राजस्व पक्ष में, अप्रैल-अगस्त 2012 के दौरान प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत निवल संग्रहण में सुधार हुआ जो मुख्यतः एक वर्ष पूर्व की तुलना में रिफंड की राशि कम रहने, संग्रहण की वृद्धि दर वर्ष के लिए अनुमानित दर से अधिक रहने के कारण था (चार्ट II.3)।

चार्ट II.2: योजनाबद्ध निवेश में उद्योगों का हिस्सा



सारणी II.7: केन्द्र सरकार के अप्रैल-अगस्त 2012 के वित्त

(₹ बिलियन)

मद	2011-12 (आरई)	2012-13 (बीई)	अप्रैल-अगस्त की राशि		बजट अनुमान की तुलना में प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	(राशि)		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राजस्व प्रतियां (i+ii)	7669.9	9356.9	1885.5	2227.3	23.9	23.8	-35.2	18.1
i) कर राजस्व (निवल)	6422.5	7710.7	1449.0	1750.6	21.8	22.7	4.6	20.8
ii) करेतर राजस्व	1247.4	1646.1	436.6	476.7	34.8	29.0	-71.3	9.2
2. गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	297.5	416.5	101.4	50.8	18.4	12.2	85.1	-49.9
3. गैर-योजना व्यय	8921.2	9699.0	3402.2	4174.0	41.7	43.0	9.3	22.7
जिसमें से								
i) ब्याज का भुगतान	2756.2	3197.6	1002.4	1137.7	37.4	35.6	17.1	13.5
ii) खाद्यान्न सब्सिडी	728.2	750.0	282.2	451.0	46.6	60.1	-11.7	59.8
iii) उर्वरक सब्सिडी	672.0	609.7	263.1	377.1	52.6	61.8	20.0	43.3
iv) पेट्रोलियम सब्सिडी	684.8	435.8	10.3	396.1	4.4	90.9	20.5	-
4. योजना व्यय	4266.0	5210.3	1320.0	1479.5	29.9	28.4	-3.3	12.1
5. राजस्व व्यय	11619.4	12861.1	4185.5	5001.7	38.1	38.9	7.0	19.5
6. पूंजीगत व्यय	1567.8	2048.2	536.7	651.9	33.4	31.8	-5.1	21.5
7. कुल व्यय	13187.2	14909.3	4722.2	5653.5	37.5	37.9	5.5	19.7
8. राजस्व घाटा	3949.5	3504.2	2300.0	2774.4	74.9	79.2	129.2	20.6
9. सकल राजकोषीय घाटा	5219.8	5135.9	2735.2	3375.4	66.3	65.7	80.6	23.4
10. सकल प्राथमिक घाटा	2463.6	1938.3	1732.8	2237.7	119.6	115.4	163.3	29.1

स्रोत: लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय।

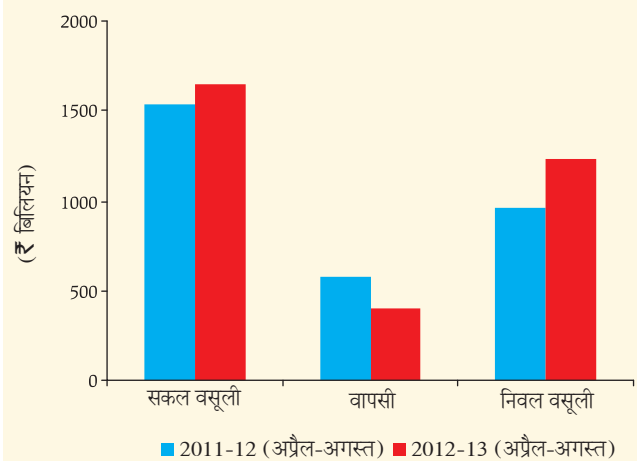
परंतु, अवधि के दौरान परोक्ष करों के संग्रहण की वृद्धि दर में कमी आई। औद्योगिक वृद्धि तथा विदेश व्यापार में आई गिरावट ने क्रमशः केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के संग्रहण को प्रभावित किया। सेवा कर की दरों में वृद्धि होने के साथ-साथ जुलाई 2012 से सेवा कर के आधार में बढ़ोतरी होने से अवधि के दौरान सेवा कर राजस्व में

तेजी से वृद्धि हुई। पूरे वर्ष के लिए सकल कर - जीडीपी अनुपात के काफी कम रहने का अनुमान है जो आर्थिक वृद्धि में गिरावट आने के चलते कर संग्रहण में आई कमी को दर्शाता है।

II.10 समग्र रूप में, केंद्र की राजस्व प्राप्तियों में कुछ कमी आ सकती है। जहां तक ऋणेतर पूंजी प्राप्ति की बात है, सरकार ने हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों की अपनी इक्विटी धारिता का आंशिक विनिवेश करने की योजना अनुमोदित की है। शेयर बाजारों की तेजी को देखते हुए बजट में निर्धारित विनिवेश का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है।

II.11 2012-13 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान कुल व्यय में हुई वृद्धि 2011-12 की वृद्धि तथा 2012-13 के बजट में निर्धारित वृद्धि से अधिक थी। सब्सिडियों के संबंध में किये गये व्यय की राशि बजट अनुमान से दो-तिहाई से भी अधिक थी। पूरे वर्ष के लिए, सब्सिडी की तीन प्रमुख मदों - खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम - के मामले में अनुमान और खर्च की राशि में काफी अंतर रहने की संभावना है जिसके चलते योजनेतर व्यय बजट में तय की गई राशि से अधिक हो सकता है। अतः, राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित सीमा में रखने के लिए योजना व्यय में कटौती की संभावना है।

चार्ट II.3: केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की वसूली



स्रोत: प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

II.12 हाल में किये गए उपाय, जैसे डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या को सीमित किया जाना तथा रेलवे के माल भाड़े और यात्री किरायों के सेवा कर में लेवी, सही दिशा में उठाए गए ऐसे कई कदम हैं, परंतु राजकोषीय घाटे को वहनीय स्तर पर रखने के लिए आगे और सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में राजकोषीय समेकन की रूपरेखा संबंधी समिति (अध्यक्ष: डॉ. विजय केलकर) ने नीतिगत कार्रवाईयों की सिफारिश की है। रिपोर्ट में उन उपायों तथा कार्रवाईयों की दिशा संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के निर्धारण के अनुसार सरकार ने सितंबर 2012 में संसद में व्यय के मध्यावधि ढांचे से संबंधित वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसमें अंतर्निहित अवधारणाओं तथा संबंधित जोखिमों का उल्लेख करते हुए व्यय संबंधी संकेतकों के लिए त्रिवर्षीय रोलिंग टारगेट का निर्धारण किया गया है।

II.13 हाल में कीमतों में किए गए संशोधनों तथा नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की संख्या संबंधी सीमा के बावजूद तेल तथा विपणन कंपनियों की कम वसूली की राशि बजट अनुमानों से अधिक रहने की संभावना है। यद्यपि बजट में 2012-13 में उर्वरक की सब्सिडी की राशि में स्पष्ट कमी लाने का सरकार का अनुमान था, यह राशि पहले ही पूरे वर्ष के बजट अनुमान से भी अधिक हो गई है। सरकारी स्रोतों के अनुसार 2012-13 में खाद्य सब्सिडी की राशि ₹924.9 बिलियन रहने का अनुमान किया गया है जो बजट अनुमानों से लगभग 24 प्रतिशत अधिक है।

II.14 राजकोषीय समेकन के लिए सरकारी व्यय के युक्तिकरण और प्राथमिकताओं के पुनः निर्धारण की जरूरत है। रणनीतिगत दृष्टि से, सब्सिडियों पर होने वाले समग्र व्यय को सीमित किए जाने तथा नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप बेहतर लक्ष्य-निर्धारण तथा वितरण की जरूरत है। खाद्य-वस्तुओं, उर्वरकों तथा पेट्रोलियम की सब्सिडी की राशि के नकद रूप में सीधे अंतरण से सब्सिडी को कम करने में मदद मिलेगी।

राज्य वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन का राज्य वित्त पर मध्यावधि से दीर्घावधि में असर पड़ सकता है

II.15 राज्यों के समेकित प्रमुख घाटा संकेतकों में 2011-12 (सं. अ.) की तुलना में 2012-13 के बजट में सुधार होने की संभावना है

जिससे तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय समेकन को आगे बढ़ाने की मंशा प्रकट होती है (सारणी II.8)। 2012-13 के बजट में राज्यों के समेकित राजस्व अधिशेष में वृद्धि होने का अनुमान किया गया है जो मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के जरिए होगी। राजस्व लेखा में सुधार के चलते राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा प्रत्येक में जीडीपी के 0.2 प्रतिशत के बराबर कमी आने की संभावना है, साथ ही इससे उच्चतर पूंजी परिव्यय के लिए संसाधन उपलब्ध होगा। 2012-13 में राजस्व व्यय - जीडीपी अनुपात में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। यह कमी सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं, दोनों से जुड़े विकास के घटक में कम वृद्धि के जरिए की जाएगी।

II.16 राज्य वितरण कंपनियों की वित्तीय पुनर्गठन की हाल में घोषित योजना में उनकी वित्तीय स्थिति को पलटने की रणनीति का प्रस्ताव किया गया है। घोषित योजना के अनुसार, ऐसी कंपनियों की उधारदाता संस्थाओं के प्रति स्थित बकाया अल्पावधि देयताओं

सारणी II.8: प्रमुख घाटा संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5
केन्द्र				
2010-11	1.8	3.3	4.9	52.8
2011-12 आरई	2.8	4.5	5.9	51.9
	(2.7)	(4.3)	(5.8)	
2012-13 बीई	1.9	3.4	5.1	-
राज्य				
2010-11	0.5	-0.1	2.1	23.4
2011-12 आरई	0.8	-0.1	2.3	22.5
2012-13 बीई	0.6	-0.4	2.1	21.8
संयुक्त रूप में				
2010-11	2.4	3.2	6.9	66.0
2011-12 आरई	3.6	4.4	8.2	65.6
2012-13 बीई	2.6	3.0	7.1	-

आरई: संशोधित अनुमान, बीई: बजट अनुमान।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक (-) चिन्ह अधिशेष दर्शाता है।

2. केन्द्र और संयुक्त बकाया देयताओं में केन्द्र की बाह्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना चालू विनियम दर पर की गई है।

3. कोष्ठक में दिया गया आंकड़ा अनंतिम लेखा है।

स्रोत: केन्द्रीय और राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

को कंपनियों द्वारा जारी बांडों में रूपांतरिक किया जाएगा और ऐसे बांडों पर सरकार की गारंटी होगी। ये बांड 2-5 वर्षों में ले लिये जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा इन्हें विशेष प्रतिभूतियों में रूपांतरित किया जाएगा। यह पुनर्गठन/ पुनःसूचीकरण राज्य वितरण कंपनियों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार तथा कंपनियों द्वारा कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने पर निर्भर करेगा। अतः वित्तीय पुनर्गठन योजना का राज्य वित्त पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मूलधन की चुकौती के लिए तीन से पांच वर्ष का स्थगनादेश है, यहां तक कि ब्याज की राशि अगले वित्तीय वर्ष में ही देय होगी। परंतु इससे राज्य वित्त पर मध्यावधि तथा दीर्घावधि में असर पड़ेगा।

वित्तीय समेकन तथा निवेश में बढ़ोतरी वृद्धि दर को फिर से आगे ले जाने की कुंजी है

II.17 राजकोषीय घाटे के ऊंचे स्तर ने समष्टि-आर्थिक माहौल को प्रभावित किया है और यह निवेश में गिरावट आने का कारण भी रहा है। वित्तीय समेकन की विश्वसनीय रणनीति इस समय सामने है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए और उपाय किए जाने की जरूरत है। निवेश में आए धीमेपन के चलते 2012-13 के दौरान समग्र मांग की स्थिति कमजोर रही। ढांचागत बाधाओं को दूर करने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के लिए किए गए कई उपायों से निवेश के वातावरण में सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। निवेश से जुड़ी ढांचागत बाधाएं दूर होने पर, आगे चलकर निवेश मांग में कुछ बढ़ोतरी होगी।